

मंथन-8

हिंदी में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला

हिमालय का कोप

18 फरवरी, 2023 | दोपहर 2.00-3.30



डाउन टू अर्थ

धंसते जोशीमठ से उठे सवाल

- राजू सजवान



मंथन-8

जोशीमठ, एक नजर

- आठवीं सदी में आदिशंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ पीठ की स्थापना की
- समुद्र तल से 6150 फुट की ऊंचाई पर बसा है जोशीमठ
- मोरेन व लैंडस्लाइड के मलबे पर बसा है, यही वजह है कि यह कमजोर है
- शहर की आबादी लगभग 25 हजार है
- 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद यहां सेना की मौजूदगी बढ़ाई गई
- बद्रीनाथ, श्री हेमकुंड साहिब, औली, फूलों की घाटी का प्रवेश द्वार है



मंथन-8

आपदा की अनदेखी

- 1976 में भूधंसाव, आयुक्त मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट
- 2005-06 में तपोवन-विष्णुगाड़ परियोजना के विरोध में जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का गठन, सरकार की अनदेखी
- फरवरी 2021 में ग्लेशियर टूटने से ऋषिगंगा में बाढ़ ने क्षति पहुंचाई
- जून 2021 में भारी बारिश से रैणी व आसपास के इलाकों में आपदा
- नवंबर 2021 में जोशीमठ के कुछ घरों में दरारें, लेकिन हाइड्रो प्रोजेक्ट व हेलंग बाइपास का काम चलता रहा



मंथन-8

किस हाल में है जोशीमठ

- 865 घरों में दरारें, 243 परिवारों को विस्थापित किया गया
- निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं
- डेढ़ माह बाद भी अस्थायी आवास नहीं बनाए जा सके हैं
- लोगों को होटलों, राहत शिविरों में ठहराया जा रहा है
- अनुमान है कि जोशीमठ का लगभग 30 फीसदी हिस्सा रहने लायक नहीं रहेगा
- अब तक पुनर्वास नीति नहीं बनी है



मंथन-8



डाउन टू अर्थ

जोशीमठ से उठे सवाल

- सबसे बड़ा सवाल, भूधंसाव क्यों हो रहा है
- 6 एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन रिपोर्ट जारी क्यों नहीं की जा रही है
- नवंबर 2021 के बाद से भूधंसाव की घटनाओं की अनदेखी क्यों की गई और किसी को जिम्मेवार क्यों नहीं ठहराया गया
- किसे बचा रही है सरकार
- इन सवालों का जवाब मिलने से केवल जोशीमठ ही नहीं, बल्कि सभी हिमालय राज्यों के लिए विकास का मॉडल तैयार किया जा सकता है



मंथन-8



डाउन टू अर्थ

खतरे में हिमालय

- जोशीमठ ही नहीं, उत्तराखंड के लगभग सभी बड़े शहर, 500 से अधिक गांव खतरे की जद में हैं
- भूधंसाव की खबरें कश्मीर से भी आ रही हैं, डाउन टू अर्थ ने पिछले साल हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह का विस्थापन देखा था
- बेहद कमजोर और संवेदनशील है हिमालय, करीब 5 करोड़ साल पहले हिमालय बनना शुरू हुआ, अभी भी हिमालय का निर्माण चल रहा है
- जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का असर, भारत में से सबसे अधिक



मंथन-8

हिम बिना हिमालय

- बढ़ती गर्मी के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। एक अध्ययन के मुताबिक औसतन हर साल 8 अरब टन बर्फ पिघल रही है
- उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पानी का संकट बढ़ रहा है, वहीं हिमालयी नदियों में बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं
- बाढ़ नदियों के किनारों को कमजोर कर रही है, अलकनंदा उदाहरण है, जिसने जोशीमठ व आसपास के इलाकों को कमजोर किया
- हिमालयी राज्यों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं



मंथन-8



डाउन टू अर्थ

हिमालय पर बोझ

- आठ देशों में फैले हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र की सबसे बड़ी आबादी भारत में रहती है
- भारत में हिमालयी राज्यों में लगभग 5 करोड़ लोग रहते हैं
- हिमालय में शहरी आबादी की वृद्धि दर 34.6% है, जो देश की औसत वृद्धि (31.8%) से अधिक है
- जिस तरह हिमालयी राज्यों में बेलगाम पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, अनुमान है कि 2025 में पर्यटकों की संख्या 24 करोड़ पार हो जाएगी
- पहाड़ी जिलों में वन आवरण में 1082 वर्ग किमी की गिरावट आई



मंथन-8



डाउन टू अर्थ

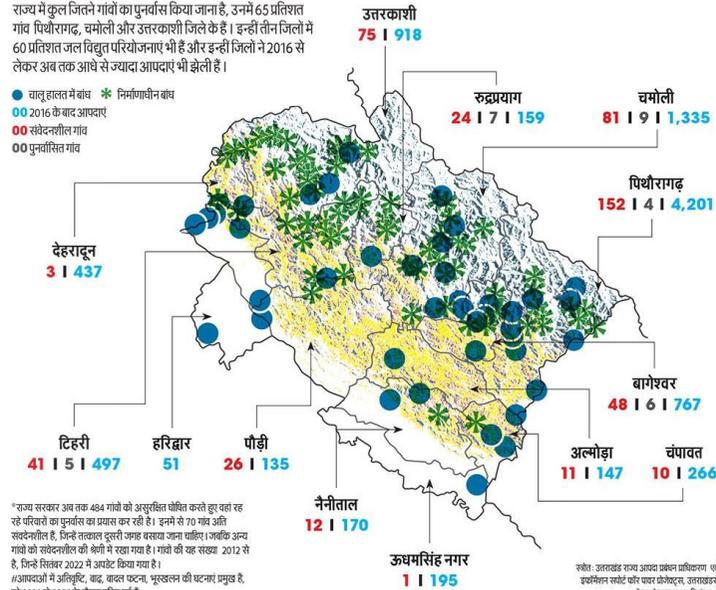
विकास की दरारें

- हिमालय से निकलने वाली नदियों पर बांध बनाकर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स विनाश की पटकथा लिख रहे हैं

त्रासद भरा विकास

राज्य में कुल जितने गांवों का पुनर्वास किया जाना है, उनमें 65 प्रतिशत गांव पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिले के हैं। इन्हीं तीन जिलों में 60 प्रतिशत जल विद्युत परियोजनाएं भी हैं और इन्हीं जिलों ने 2016 से लेकर अब तक आधे से ज्यादा आपदाएं भी झेली हैं।

- जालू हालत में बांध * निर्माणगामी बांध
- 00 2016 के बाद आपदाएं
- 00 संवेदनशील गांव
- 00 पुनर्वासित गांव



* राज्य सरकार अब तक 484 गांवों को अस्थायी बंधों से बचाने का काम कर चुकी है। इनमें से 70 गांव अति संवेदनशील हैं, जिन्हें तत्काल दूसरी बांध बनाना चाहिए। जबकि अन्य गांवों को संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। गांवों की यह संख्या 2012 से है, जिन्हें सितंबर 2022 में अपडेट किया गया है।
#आपदाओं में अतिरिक्त, बाढ़, बल्लू चट्टान, भूस्खलन की घटनाएं प्रमुख हैं, जो 2016 से 2021 के दौरान घटित हुई हैं।

स्रोत: उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं मिनेटोपेटियल इन्फ्लेमेशन सर्वेय ऑफ चार लोकेशन, उत्तराखंडकेस असीकेशन सर्वे, देहरादून द्वारा सितंबर 2018 में प्रकाशित।



मंथन-8



डाउन टू अर्थ

समाधान

- हिमालय के विकास में वैज्ञानिक अध्ययनों की अनदेखी का रास्ता छोड़ना होगा
- हिमालय में बहुमंजिला व कंक्रीट से बनी इमारतों के निर्माण रोकना होगा
- पर्यटकों की संख्या पर अंकुश लगाना होगा
- बड़े बांध व सुरंग आधारित हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को रोकना होगा
- सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर पहाड़ों का कटान रोकना होगा
- जंगलों को काटना बंद करना होगा



मंथन-8



डाउन टू अर्थ